

पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 22/2018

अपीलांट

1. वेलाराम पुत्र तेजारामजी उम्र 38 वर्ष
2. रणछोडराम पुत्र तेजारामजी उम्र 28 वर्ष
3. परशुराम पुत्र तेजारामजी उम्र 37 वर्ष
4. गोपालकृष्ण पुत्र तेजारामजी उम्र 27 वर्ष
5. तेजाराम पुत्र गोमारामजी उम्र 64 वर्ष समस्त जातियान चौधरी निवासीयान चवरछा, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. अमीया देवी पत्नी छोगाजी जाति चौधरी, निवासी गांगावा तहसील आहोर जिला जालोर।
2. उज्जी देवी पत्नी उमाजी, जाति चौधरी, निवासी हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर।
3. सदणो देवी पत्नी कसनाजी, जाति चौधरी, निवासी मणादर तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
4. भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री चुन्नीलाल पुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04

—: निर्णय :-

दिनांक : 16.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा वाद संख्या 62/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत

आशाराम डूडी/प्राधिकारी
पाली

22/2018

वेलाराम वगैरह बनाम अमीया वगैरह

पेज संख्या 2/4

धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चवरछा पटवार हल्का चवरछा, भू-अभिलेख निरीक्षक गुडा बालतोन, तहसील आहोर के खसरा नंबर 534, 535, 506, 510, 511 कुल रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार है। अपीलांट संख्या 5 ने वादग्रस्त आराजी 510, 511, 534, 535, 506 कुल रकबा 10.45 हैक्टेयर आराजी जरिये रजिस्टर्ड गिफ्टडीड नग दो दिनांक 26.05.2014, 26.06.2014 को अपीलांट संख्या 02 से 05 के पक्ष में करवाकर उन्हे भौतिक कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से अपीलांट संख्या 02 से 05 का ही कब्जा व खातेदारी म्यूटेशन नंबर 496 राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या 02 से 05 वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबध में पूर्व में एक वाद सहायक कलक्टर जालोर के समक्ष म्यूटेशन नंबर 222 के विरुद्ध तेजाराम बनाम सदणो वगैरा चला, जिसमे रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 पक्षकार थी, जिन्होंने इकबाली जवाब पेश कर जाहिर किया था कि हमारी माता सौदीदेवी ने तेजा को दिनांक 5.07.79 को जाति रिवाज से गोद लिया है। गोमा की आज से करीब 44 साल पूर्व मृत्यु हो चुकी है। व उनकी पत्नी सौदी को भी 40 साल फौत हुए हो चुके हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 2005 से पहले दोनो की मृत्यु होने के कारण पुत्रियो को कोई हक उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तेजाराम अकेला पक्षकार था, जिसको नोटिस तामिल नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तेजाराम को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में विधि विरुद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चवरछा पटवार हल्का चवरछा, भू-अभिलेख निरीक्षक गुडा बालतोन, तहसील आहोर के खसरा नंबर 534, 535, 506, 510, 511 कुल रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 गोमा की जायंदा पुत्रियां हैं। जिससे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित हो जाते हैं। अपीलांट संख्या 5 ने द्वितीय सेटलमेंट के अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलावट कर अपने आप को गोमा का गोद पुत्र बनकर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम गलत ढंग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित होने का



वकील/प्रतिवादी
श्री

22/2018

वेलाराम वगैरह बनाम अमीया वगैरह

पेज संख्या 3/4

हवाला देते हुए वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। रैस्पोजेन्ट संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा चवरछा पटवार हल्का चवरछा, भू-अभिलेख निरीक्षक गुडा बालतोन, तहसील आहोर के खसरा नंबर 534, 535, 506, 510, 511 कुल रकबा 56 बीघा 9 बिस्वा के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or



अधिवक्ता प्र. व. प्राधिकारी
जापुर

22/2018

वेलाराम वगैरह बनाम अमीया वगैरह

पेज संख्या 4/4

settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनों पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान हैं। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्ट्स मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवों के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरुद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा वाद संख्या 62/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशाराम डडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली